RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

# इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 08 JANUARY TO 14 JANUARY 2020 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 05 ■ अंक 20 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

इराक में अमेरिकी बेस पर ईरान के हमले के बाद कच्चे तेल का भाव चढ़ा Page 2

सरकार की नीतियों के खिलाफ दस केंद्रीय ट्रेड यूनियन हड़ताल पर Page 5

अब तक 12,000 टन प्याज का आयात, राज्यों को 49-58 रुपये किलो के भाव पेश: पासवान Page 7

editoria!

## फील गुड इंफ्रास्ट्रक्चर

नए साल की शुरुआत के साथ देशवासियों को फील गुड का अहसास कराते हुए केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर एक महत्वाकांक्षी घोषणा की है। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि देश में पहली बार एक नैशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) तैयार की गई है, जिसके तहत अगले पांच वर्षों में 105 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के अलावा केंद्र और राज्य सरकारों ने पिछले छह सालों में बुनियादी संरचना विकास पर 51 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए गए भाषण में आधारभूत संरचना पर 100 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की बात कही थी। इसके बाद एक टास्क फोर्स गठित की गई थी, जिसने तमाम पक्षों के साथ 70 बैठकें कर 102 लाख करोड़ की परियोजनाओं की पहचान की है। कुछ ही सप्ताह में इस पाइपलाइन में तीन लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं और जुड़ जाएंगी जिससे एनआईपी 105 लाख करोड़ रुपये की हो जाएगी। जो परियोजनाएं इसमें शामिल हैं उनका संबंध बिजली, रेलवे, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि से है। एनआईपी में केंद्र और राज्य, दोनों की परियोजनाओं की हिस्सेदारी 39-39 फीसदी है जबकि निजी क्षेत्र की परियोजनाओं की हिस्सेदारी 22 फीसदी है, जिसे 2025 तक बढ़ाकर 30 फीसदी तक करने की योजना है। वित्त मंत्री ने दावा किया कि इससे रोजगार के बहुत सारे अवसर पैदा होंगे और जीवन सुगमता बढ़ेगी। बहरहाल, वित्त विशेषज्ञों ने सवाल उठाया है कि परियोजनाओं के लिए राशि कहां से जुटाई जाएगी? वित्त मंत्री ने स्वीकार किया है कि मौजूदा आर्थिक सुस्ती को देखते हुए एनआईपी के लिए धन जुटाना आसान नहीं होगा, फिर भी सरकार ने इसके लिए कुछ रास्ते सोचे हैं। इसमें शामिल परियोजनाओं की प्रगति बुनियादी तौर पर बैंकों और बॉन्ड मार्केट से उठाए गए ऋण पर निर्भर करेगी। इसके अलावा इनके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्टर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाया जाएगा। वित्त मंत्री के अनुसार एक सालाना ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सम्मेलन का सिलसिला शुरू किया जाएगा जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें अपनी परियोजनाओं के बारे में निवेशकों को जानकारी देंगी और उन्हें इनमें निवेश के लिए प्रेरित करेंगी। डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक अफेयर्स में सचिव अतनु चक्रवर्ती के अनुसार फंड की समस्या नहीं होगी। पहले वर्ष में सिर्फ 18.44 लाख करोड़ के प्रॉजेक्ट शुरू किए जाएंगे। दूसरे साल खर्च बढ़कर 21.62 लाख करोड़ हो जाएगा। आम तौर पर इन परियोजनाओं में ऋण-इक्विटी का अनुपात 1:2 का रहेगा। फिर इस ग्रैंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान में शामिल तमाम सरकारी कंपनियां अपने आंतरिक संसाधनों का भी इस्तेमाल करेंगी। इसके साथ ही सरकार ने विदेशी निवेश को आमंत्रित करने के लिए मौजूदा रेलवे, ऊर्जा और हाईवे परियोजनाओं को अलग-अलग तरीकों से बाजार में उतारने का भी फैसला किया है। उम्मीद करें कि ये परियोजनाएं देश की आर्थिक सुस्ती दूर करने में सहायक होंगी।

# ईरान ने इराक में अमेरिकी सेना पर दागीं मिसाइलें, भारत की बढ़ी टेंशन

**नई दिल्ली। ईरान और अमेरिका में तनाव बढ़ने के बाद पूरी दुनिया सहमी हुई है। तेहरान ने इराक में अमेरिकी सेनाओं पर मिसाइलें दागीं और दावा किया इस हमले में 80 लोग मारे गए हैं। ईरान ने कहा है कि वह अपने जनरल कासिम सुलेमानी की मौत बदला लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्टिकल 51 के तहत यह कार्रवाई कर रहा है। ईरान के इस ऐक्शन ने पूरी दुनिया के शेयर बाजार में हलचल मचा दी है। आइए जानते हैं कि भारत पर इस तनाव का क्या पड़ सकता है असर...**

### रिश्तों पर पड़ सकता है असर

भारत का अमेरिका और ईरान दोनों देशों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में तेहरान की यात्रा की थी। जबकि राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी से बात की थी। अगर ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खत्म नहीं होगा तो भारत के लिए मुश्किल वाले हालात पैदा हो सकते हैं।

### पश्चिम एशिया में रह रहे भारतीयों को मुश्किल

ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की अमेरिकी हमले में हत्या के बाद पश्चिमी एशिया में अमेरिका और ईरान के तनाव का बुरा असर पड़ सकता है और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। भारत पर इसका सीधा असर विदेश नीति, एनर्जी से जुड़े पक्ष और लगभग 1 करोड़ भारतीयों के रोजगार पर पड़ सकता है। खाड़ी देशों में भारत के एक करोड़ के करीब कामगार इस वक्त मौजूद हैं। भारत को अपने इन नागरिकों की सुरक्षा की भी चिंता करनी होगी। 1990-1991 में खाड़ी संकट के वक्त भारत के हजारों की संख्या में फंसे भारतीयों को कुवैत और दूसरी जगहों से निकालना

बहुत चुनौतीपूर्ण रहा था। वैसे ही हालात फिर से बने तो भारत की मुश्किलें इस साल और बढ़ जाएंगी।

### तेल की कीमतों में होगी बढ़ोतरी

ईरान के ऐक्शन के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में दो डॉलर से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। भारत अपनी जरूरत का लगभग पूरा तेल खाड़ी के देशों से ही आयात करता है। इस तनाव से उसके आयात पर असर पड़ेगा और तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं।

### सोने के दाम रेकॉर्ड स्तर पर

ईरान के ऐक्शन के बाद जहां शेयर बाजारों में गिरावट का रुख है वहीं, सोने में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ पैसा लगा रहे हैं। शर्ट पर सोने का भाव 41 हजार से ज्यादा पहुंच गया है।

### भारत सरकार ने जारी की अडवाइजरी

इराक में मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीयों को अगले आदेश तक इराक की यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में इराक में रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और वहां यात्रा न करने की सलाह दी गई है। बगदाद में हमारे हाई कमीशन और इरबिल स्थित काउंसुलेट सामान्य कामकाज जारी रखेंगे और इराक में रह रहे भारतीयों को सभी प्रकार की सेवाएं जारी रखेंगे।

### व्यापार के मोर्चे पर भी मुश्किल

ईरान का चाबहार पोर्ट है जिसको भारत के सहयोग से बनाया गया है। दरअसल, चारों तरफ से जमीन से घिरे अफगानिस्तान तक सीधी पहुंच देने में पाकिस्तान आनाकानी करता था। इसका तोड़ निकालने के लिए भारत ने ईरान के रास्ते अफगानिस्तान सामान भेजने का फैसला किया। इसके लिए भारत में ईरान के चाबहार पोर्ट में अरबों रुपये का निवेश किया और ईरान से अफगानिस्तान तक सड़क मार्ग का भी निर्माण कराया। अब ईरानी पोर्ट अफगानिस्तान को आसानी से समुद्र तक पहुंच देता है। अगर ईरान और अमेरिका में तनाव बढ़ता है तो फिर भारत के लिए व्यापार के मोर्चे पर भी मुश्किल आ सकती है।

US-Iran Tension

# अमेरिका-ईरान में तनाव से घबराए दुनियाभर के शेयर बाजार, सेंसेक्स 350 और निफ्टी 100 अंक लुढ़का

**नई दिल्ली। एजेंसी**

कुद्स फोर्स के प्रमुख मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद अब ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। इराक स्थित अमेरिकी एयरबेस पर ईरान के मिसाइल अटैक की खबरों के बाद दुनियाभर के शेयर बाजार में घबराहट बढ़ गई है। एशियाई बाजारों में 2 फीसदी तक की गिरावट है। वहीं भारतीय शेयर बाजार भी इससे अछूता नहीं. BSE का 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 350 अंक और NSE का 50 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 100 अंक लुढ़क गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसे में अच्छे फंडामेंटल वाले शेयरों को निचले स्तर पर खरीद सकते हैं।

एशियाई बाजारों में भारी गिरावट- अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से जापान का प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स निक्केई 300 अंक टूट गया है। वहीं दक्षिण कोरिया के प्रमुख इंडेक्स कोस्पी में 1 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आ गई है। इसके अलावा हांग कांग के हैंग-सैंग में 250 अंक की गिरावट है. चीन का प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स शंघाई भी 1 फीसदी नीचे आ गया है। इससे पहले अमेरिकी बाजारों में भी भारी गिरावट देखने को मिली है. डाओ जोंस 120 अंक की गिरकर 28584 के स्तर पर बंद हुआ। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट जारी- दिग्गज शेयरों के साथ ही मिड और स्मॉलकैप शेयर में भी बिकवाली नजर आ रही है। बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 0.34 फीसदी और स्मॉलकैप इंडेक्स 0.21 फीसदी की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। तेल-गैस शेयरों में भी आज भारी बिकवाली नजर आ रही है.। बीएसई का ऑयल एंड गैस इंडेक्स 1.05 फीसदी की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है।

# इराक में अमेरिकी बेस पर ईरान के हमले के बाद कच्चे तेल का भाव चढ़ा

*नई दिल्ली। ईरान द्वारा इराक में अमेरिकी बेस पर किए गए मिसाइल हमले के बाद तेल की कीमत में काफी उछाल आया है। ईरान के हमले के बाद तेल की कीमत में करीब 4.5 फीसदी का उछाल आया। WTI इंडेक्स पर तेल की कीमत में 4.53 फीसदी उछलकर 65.54 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच चुका था। इधर, शुर्ई पर कच्चे तेल में कारोबार की शुरुआत 25 रुपये प्रति बैरल तेजी के साथ हुआ और नई दर 4,519 रुपये प्रति बैरल पर पहुंच गया। 11 बजे तक दर में और इजाफा हुआ और यह 84 रुपये प्रति बैरल की तेजी के साथ 4,578 रुपये प्रति बैरल तक पहुंच गया। सुबह 12.35 बजे जनवरी अनुबंध वाला तेल शुर्ई पर 70 रुपये की तेजी के साथ 4564 रुपये प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था। कारोबार के दौरान आज यह 4590 रुपये प्रति बैरल तक पहुंच गया था। 12.40 बजे ब्रेंट ऑयल 0.73 डॉलर (1.10 फीसदी) की तेजी के साथ 69.01 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था। आज यह 68.32 डॉलर प्रति बैरल पर खुला था। कारोबार के दौरान एक समय यह 71.28 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया था।*

### पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर

कच्चे तेल की कीमत में भले ही उछाल आया हो लेकिन आज पेट्रोल और डीजल की कीमत पर इसका कोई असर नहीं दिखा है। छह दिनों तक लगातार कीमत में उछाल के बाद आज पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे। छह दिनों में पेट्रोल 60 पैसा और डीजल 83 पैसा प्रति लीटर तक महंगा हुआ। आज कच्चा तेल महंगा हुआ जिसका असर पेट्रोल डीजल पर जरूर दिखाई देगा।

8 जनवरी को दिल्ली में पेट्रोल 75.74 रुपये प्रति लीटर और डीजल 68.79 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 81.33 रुपये और डीजल 72.14 रुपये, कोलकाता में पेट्रोल 78.33 रुपये और डीजल 71.15 रुपये, चेन्नै में पेट्रोल 78.69 रुपये और डीजल 72.69 रुपये, गुरुग्राम में पेट्रोल 75.03 रुपये और डीजल 67.66 रुपये जबकि नोएडा में पेट्रोल 76.83 रुपये और डीजल 69.06 रुपये है।

### शेयर मार्केट में गिरावट

बीएसई के सेंसेक्स में बुधवार को शुरुआती कारोबार में 185 अंक से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। कारोबारियों के मुताबिक अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरानी हमले के चलते पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने की आशंका के चलते बाजार दबाव में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के 30 शेयरों का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 187.36 अंक यानी 0.46 प्रतिशत गिरकर 40,682.11 अंक पर आ गया। इसी प्रकार, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के 50 शेयरों का संवेदी सूचकांक निफ्टी भी शुरुआती दौर में 68.60 अंक यानी 0.57 प्रतिशत फिसलकर 11,984.35 अंक पर आ गया। कारोबारियों के मुताबिक, ईरान के अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाये जाने के बाद पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ गया। इस वजह से घरेलू शेयर बाजार में गिरावट का रुख देखने को मिला।

### इराक में अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमला

ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान ने अमेरिका को जवाब देते हुए इराक में उसके बेस कैम्प पर हमला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दो एयरबेस पर हमला किया गया है। ईरानी प्रेस टीवी का दावा है कि इस हमले में 80 लोग मारे गए हैं जबकि अमेरिका की तरफ से अभी जान-माल के नुकसान को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप भी ट्वीट कर चुके हैं कि सब ठीकठाक है।

## कोयले पर प्रदूषण कर हटाने का प्रस्ताव नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए जोखिम भरा :फिच

**नई दिल्ली। एजेंसी**

रेटिंग एजेंसी फिच की राय में भारत में कोयले पर कार्बन कर हटाने का प्रस्ताव देश के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए बड़ा जोखिम भरा है। फिच ने सोमवार को कहा कि भारत सरकार ने कर्ज के बोझ तले दबे बिजली उद्योग को राहत देने के लिए कोयले पर कार्बन कर समाप्त करने का प्रस्ताव किया है। यह कर प्रति टन 400 रुपये की दर से लागू किया जाता है। यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जबकि नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बोलियों में इस क्षेत्र की बिजली की दरें काफी नीचे आ चुकी है। फिच सोल्यूशन्स ने अपनी एक टिप्पणी में कहा है कि कोयले पर कार्बन कर हटाने का प्रस्ताव " नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की वृद्धि को प्रभावित करेगा।" उसकी राय में यह कर हटने से कोयला आधारित बिजली सस्ती होगी और इस काम में कोयले का इस्तेमाल बढ़ेगा। भारत के बिजली उत्पादन क्षेत्र में कोयले की भूमिका बहुत बड़ी है। अनुमान है कि 2029 तक बिजली उत्पादन क्षमता में कोयले पर आधारित बिजली घरों का हिस्सा 70 प्रतिशत से थोड़ा ही कम रहेगा। उसके मुकाबले पर बिजली को छोड़ बाकी नवीरकणीय स्रोतों की बिजली उत्पादन क्षमता 15.6 प्रतिशत होगी।

**अमेरिका-ईरान टेंशन**

## अगर 10 डॉलर महंगा हो गया तेल तो जानें कितनी बढ़ जाएगी महंगाई

**नई दिल्ली। एजेंसी**

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से पूरा विश्व प्रभावित हुआ है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। जैसे-जैसे यह टेंशन बढ़ेगा, हमारी जेब पर बोझ बढ़ेगा। सबसे पहले तेल महंगा होगा और भारत जरूरत का 80 फीसदी आयात करता है। पिछले छह दिनों में पेट्रोल और डीजल करीब 85 पैसे तक महंगा हो चुका है। संभावना है कि आने वाले दिनों में यह और महंगा होगा।10 डॉलर महंगा होगा तेल तो 0.40 फीसदी बढ़ेगी महंगाई

एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर कच्चा तेल 10 डॉलर प्रति बैरल महंगा होता है तो हर महीने भारत का आयात बिल 1.5 अरब डॉलर बढ़ जाएगा। महंगे तेल का सीधा असर रीटेल महंगाई पर पड़ता है और यह 0.40 फीसदी से बढ़ जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था पहले से मांग में कमी से गुजर रही है। ऐसे में अगर महंगाई बढ़ जाती है तो आर्थिक सेहत और बिगड़ जाएगी।

### कच्चा तेल 70 डॉलर तक पहुंचा

दिसंबर महीने में ध्ईं देशों ने पहले ही कच्चे तेल का उत्पादन करीब 50 हजार बैरल रोजाना घटा दिया था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में यह 70 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। महंगे तेल ने सरकार की चुनौती बढ़ा दी है।

### निवेशकों के एक दिन में डूबे 3 लाख करोड़

मार्केट में अनिश्चितता के माहौल के कारण निवेशक घबरा गए हैं और शेयर मार्केट से तेजी से पैसा निकाल रहे हैं और सुरक्षित निवेश की ओर रुख कर रहे हैं। यही वजह है कि 6 जनवरी को सेंसेक्स 788 अंक और निफ्टी 234 अंकों की भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। एक दिन में निवेशको के करीब 3 लाख करोड़ रुपये डूब गए। दूसरी तरफ सोने में जबर्दस्त लिवाली के कारण यह 41 हजार के पार पहुंच चुका है।

### पाकिस्तान में एकबार फिर मिलिट्री ट्रेनिंग

ईरान हमले के बाद अमेरिका एकबार फिर से पाकिस्तान में गतिविधि बढ़ाने पर फोकस किया है ताकि वह पश्चिमी एशिया को लेकर अपनी स्ट्रैटजी को और मजबूत कर सके। अमेरिका एकबार फिर से पाकिस्तान में मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू करने जा रहा है जिसे 2018 में बंद कर दिया गया था। उस समय डॉनल्ड ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठा रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका इस प्रोग्राम को बंद करने जा रहा है। भारत के लिए यह स्थिति कूटनीतिक रूप से अच्छी नहीं है।

## अमेरिका-ईरान तनाव के बीच रुपया शुरुआती कारोबार में 20 पैसे फिसला

**मुंबई।** ईरान के इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के बाद पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ने से रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 20 पैसे लुढ़क कर 72.02 रुपये प्रति डॉलर पर आ गया। अंतर बैंक विदेशी विनिमय बाजार में रुपया गिरावट के साथ खुला और शुरुआती कारोबार में गिरकर 72 रुपये प्रति डॉलर से नीचे चला गया। रुपया मंगलवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 71.82 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। अमेरिका-ईरान के बीच तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होने की आशंका से ब्रेंट कच्चा वायदा 1.32 प्रतिशत बढ़कर 69.17 डॉलर प्रति बैरल पर चल रहा था। इस बीच, बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 138.60 अंक यानी 0.34 प्रतिशत गिरकर 40,730.87 अंक पर चल रहा था। शेयर बाजार के पास मौजूद आरंभिक आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने मंगलवार को शुद्ध रूप से 682.23 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

# आउटपुट टैक्स पर ही लगेगा लेट पेमेंट का ब्याज!

***नई दिल्ली। देरी से जीएसटी जमा कराने वाले ट्रेडर्स को कई गुना ज्यादा ब्याज की वसूली से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। पहली जनवरी से लागू होने वाले जीएसटी के कई नए प्रावधानों और हालिया संशोधनों की फेहरिस्त से सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 50 में हुआ अमेंडमेंट नदारद है, जिसका ट्रेड-इंडस्ट्री को बेसब्री से इंतजार था। इसके तहत ट्रेडर्स से लेट पेमेंट पर 1.5% ब्याज की वसूली आउटपुट टैक्स के बजाय नेट पेमेंट पर वसूलने का का प्रावधान था।***

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) की ओर से जारी हालिया नोटिफिकेशंस में जुलाई में जीएसटी एक्ट में हुए कई अहम संशोधनों को लागू किया गया है। इनमें कुछ ऐसे भी हैं, जिन्हें राज्य सरकारें पहले ही नोटिफाई कर चुकी हैं और केंद्रीय स्तर पर देरी से इंडस्ट्री हैरान है। हालांकि कई अहम संशोधनों पर अभी नोटिफिकेशन नहीं आने से परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि कानूनी संशोधन की घोषणा के बाद से ही टैक्सपेयर बदलावों के अनुरूप अपना बिजनेस एडजस्ट कर बैठे हैं और उसी के मुताबिक अनुपालन भी करते आ रहे हैं। इनमें सेक्शन 50 के तहत लेट पेमेंट पर ब्याज की वसूली भी शामिल है।

जीएसटी कंसल्टेंट राकेश गुप्ता ने बताया कि अगर किसी डीलर का मंथली आउटपुट टैक्स 1 करोड़ रुपये है और इनपुट टैक्स 95 लाख है, तो उसका नेट टैक्स 5 लाख रुपये होगा। अगर यह कारोबारी छह महीने की देरी से टैक्स जमा कराए तो उसे 1 करोड़ रुपये के 1.5% मंथली के हिसाब से 9 लाख रुपये ब्याज चुकाना होगा, जबकि नेट टैक्स 5 लाख रुपये के आधार पर ब्याज वसूली से उसका ब्याज 45,000 रुपये ही होगा। जनवरी के आखिर तक भरे जाने वाले एनुअल रिटर्न से पहले ही इस टैक्स का भुगतान भी करना होगा।

बीते दो साल से इस विवादित मुद्दे पर कारोबारी अदालतों का चक्कर भी लगाते रहे हैं। करीब एक साल पहले जीएसटी काउंसिल से राहत मिलने के बाद भी कानूनी संशोधन के अभाव में यह लागू नहीं हो सका था। लेकिन जुलाई में फाइनेंस बिल के तहत इसके संसद से पास होने के बाद से कारोबारी नेट टैक्स पर अपनी देनदारी कैलकुलेट करने लगे थे, जबकि औपचारिक नोटिफिकेशन अभी नहीं आया था। 1 जनवरी से लागू होने वाले कई संशोधनों की लिस्ट में इसके नहीं होने से अब कारोबारियों को यह टेंशन भी होने लगी है कि अगर ज्यादा ब्याज पर भुगतान कर भी दें और बाद में यह नोटिफाई हो जाए तो पैसा रिफंड नहीं होगा, जैसा कि रिटर्न की लेट फीस के मामले में हुआ था। कंपोजिशन डीलर्स को तिमाही टैक्स और साल में एक बार रिटर्न का कानूनी संशोधन भी फिलहाल नोटिफाई नहीं हुआ है।

## जीएसटी को आसान बनाने में जुटे हैं 12 देशों के अधिकारी

***नई दिल्ली। बजट की तैयारी जोरों पर है। उम्मीद की जा रही है कि इसमें इनकम टैक्सपेयर्स को राहत मिल सकती है। मंगलवार को एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार टैक्स सिस्टम को ज्यादा सरल बनाने की दिशा में काम कर रही है। ईमानदार टैक्सपेयर्स के कोई परेशानी ना हो, हम इसके लिए प्रयासरत हैं।***

### सरकार हर सुझाव का स्वागत करती है- सीतारमण

CAIT (कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ) के कार्यक्रम में अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने कहा कि उएऊ सिस्टम को बेहतर बनाने को लेकर किसी तरह की सलाह का सरकार स्वागत करती है। अभी तक जितनी भी सलाह मिली हैं, उनको ध्यान में रखकर सरकार ने जरूरी कदम उठाए हैं।

### 12 से ज्यादा देशों के टैक्स अधिकारियों की मदद

जानकारी के लिए बता दें कि गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (GST) में कारोबारियों को आ रही दिक्कतें दूर करने और इसका अनुपालन आसान करने के लिए केंद्र सरकार करीब एक दर्जन देशों के जीएसटी अधिकारियों और विशेषज्ञों की मदद ले रही है। पिछले दिनों देश भर में जोनल स्तर पर स्टेकहोल्डर्स के साथ हुई बैठकों में दर्ज शिकायतों और सुझावों के आधार रिटर्न और रिफंड की प्रक्रिया और सरल करने की कवायद शुरू हो चुकी है।

### नोटिस पर DIN नंबर होना जरूरी है

सीतारमण ने कहा कि ट्रेडर्स की परेशानियां दूर करने और पारदर्शिता लाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। अब हर टैक्स नोटिस या ऑर्डर के लिए उस पर डॉक्युमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) होना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपको बिना ॲ के कोई नोटिस मिलता है तो आप उसे कूड़ेदान में फेंक दीजिए। कोई अधिकारी पूछे तो बोलिए कि हमें मिला ही नहीं। ऐसा अवैध वसूली और शोषण रोकने के लिए किया गया है।

### आंतरिक व्यापार के लिए अलग मंत्रालय

उन्होंने बताया कि सरकार ने पहली बार आंतरिक व्यापार के लिए अलग मंत्रालय का गठन किया है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत बना डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री ऐंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) व्यापारियों की पेंशन स्कीम सहित कई योजनाओं पर काम कर रहा है। यह आंतरिक व्यापार को मिल रही तमाम चुनौतियों पर भी नजर रखेगा।

## 'जीएसटी मुआवजा समाप्ति के बाद राज्यों का राजस्व अंतर पहुंच सकता है एक लाख करोड़ रुपये के पार'

***नयी दिल्ली। माल एवं सेवा कर ( जीएसटी ) के तहत मुआवजा अवधि समाप्त होने के बाद राज्यों को एकीकृत रूप से 1.23 लाख करोड़ रुपये तक के राजस्व की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक शोध संस्थान एनआईपीएफपी की एक रिपोर्ट में यह अनुमान व्यक्त किया गया है। इसमें कहा गया है कि 30 जून, 2022 को जीएसटी के तहत राज्यों के लिये उनके राजस्व नुकसान की भरपाई करने की पांच साल की अवधि समाप्त हो जाएगी।***

इसके बाद राज्यों को राजस्व वृद्धि के अनुरूप भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। जीएसटी का क्रियान्वयन एक जुलाई, 2017 को किया गया था। उस समय केंद्र ने राज्यों को एक सहमति वाले फॉर्मूला के तहत पांच साल तक राजस्व की संभावित वृद्धि में होने वाले नुकसान की भरपाई का वादा किया था। रिपोर्ट में कहा गया है, ''यदि 30 जून, 2022 के बाद जीएसटी मुआवजे की व्यवस्था समाप्त हो जाती है, तो राज्यों के राजस्व में उम्मीद के अनुरूप कर प्राप्ति और आंकड़े स्रोत विश्वसनीयता की यदि बात की जाये तो कुल मिलाकर 1,00,700 से 1,23,646 करोड़ रुपये के बीच कमी रह सकती है।'' रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे में राज्यों को 2022-23 में अपने मौजूदा संसाधनों से ही इतना राजस्व और जुटाना होगा या फिर अपने खर्चों में कमी करनी पड़ेगी। जीएसटी संग्रह में कमी तथा जीएसटी मुआवजे की जरूरत और जीएसटी मुआवजा उपकर संग्रह के अंतर की वजह से केंद्र सरकार राज्यों को समय पर जीएसटी मुआवजा जारी नहीं कर पा रही है। इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवाद छिड़ा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जीएसटी मुआवजा वापस होने और राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) संग्रह में कमी से पंजाब, ओड़िशा, गोवा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक राज्यों के वित्त पर काफी प्रभाव पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा और मेघालय जैसे छोटे राज्य भी इससे प्रभावित होंगे। जीएसटी संग्रह में कमी और एसजीएसटी संग्रह को लेकर अनिश्चितता के बीच कई राज्यों ने 15वें वित्त आयोग से जीएसटी मुआवजे की अवधि को तीन साल बढ़ाकर 2024-25 करने का आग्रह किया है।

# वित्त वर्ष 2019-20 के GDP दर का पहला अनुमान जारी

## 5% रहने का आकलन

**नई दिल्ली।** अर्थव्यवस्था में छाई सुस्ती से फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने के मद्देनजर वित्त वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) विकास दर 5% रहने का अनुमान जताया गया है। पूरे वित्त वर्ष 2019-20 के लिए विकास दर का यह पहला आकलन है। वहीं, इस वित्त वर्ष जीवीए (GVA) 4.9% रहने का अनुमान जताया गया है। यह अनुमान सरकारी आंकड़ों में लगाया गया है। इससे पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में आर्थिक वृद्धि दर 6.8% रही थी।राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने मंगलवार को राष्ट्रीय आय का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया। इसमें कहा गया है कि आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट की प्रमुख वजह विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर घटना है।जीडीपी आकलन के आंकड़े ऐसे वक्त में जारी किए गए हैं, जब भारतीय अर्थव्यवस्था में भारी सुस्ती देखी जा रही है। जीडीपी अनुमान के आंकड़ों को लेकर नीति-नियंता भी हैरान हैं।

### विनिर्माण की वृद्धि दर भी घटेगी

चालू वित्त वर्ष में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर घटकर 2% पर आने का अनुमान है। इससे पिछले वित्त वर्ष में यह 6.2% रही थी। अग्रिम अनुमान के अनुसार कृषि, निर्माण और बिजली, गैस और जलापूर्ति जैसे क्षेत्रों की वृद्धि दर भी नीचे आएगी। वहीं खनन, लोक प्रशासन और रक्षा जैसे क्षेत्रों की वृद्धि दर में मामूली सुधार का अनुमान है।

### साढ़े छह साल के निचले स्तर पर इकॉनमी

जून तथा सितंबर तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था क्रमशः 5% तथा 4.5% की दर से आगे बढ़ी है, जो साढ़े छह वर्षों का निचला स्तर है। जीडीपी विकास दर के आंकड़ों में लगातार आ रही गिरावट से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को 2019-20 के लिए विकास दर अनुमान को 7.4% से घटाकर 5% करने को मजबूर होना पड़ा था।

केंद्र सरकार आगामी 1 फरवरी को आम बजट पेश करेगी। वित्त वर्ष 2019-20 के विकास दर का दूसरा अनुमान बजट के बाद जारी किया जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में ग्रोथ रेट गिरकर 4.5 फीसदी पर पहुंच गया। तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) को लेकर जापान की वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी नोमुरा का मानना है कि विकास की रफ्तार और धीमी होगी और यह घटकर 4.3 फीसदी पर पहुंच सकती है।

### अनुमान के आधार

वित्त वर्ष 2019-20 के विकास दर के पहले अनुमान के लिए निम्न आंकड़ों को आधार बनाया गया है।

■ अप्रैल-अक्टूबर 2019 की IIP ■दूसरी तथा तीसरी तिमाही में सूचीबद्ध कंपनियों का वित्तीय प्रदर्शन ■फसल उत्पादन का अग्रिम अनुमान ■केंद्र तथा राज्य सरकारों के राजस्व ■रेलवे की यात्रियों तथा माल ढुलाई से होने वाली आय, एयर कार्गो हैंडल, कारों की बिक्री सहित कई अन्य आंकड़े।

## विदेशी मुद्रा भंडार 457.46 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर

**मुंबई।** देश का विदेशी मुद्रा भंडार 27 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में 2.520 अरब डॉलर बढ़कर 457.468 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। आरबीआई के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इससे पिछले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 45.6 करोड़ डॉलर बढ़कर 454.948 अरब डॉलर पर था। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक , विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में वृद्धि की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी आई है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 2.203 अरब डॉलर बढ़कर 424.936 अरब डॉलर पर पहुंच गयी। इस दौरान स्वर्ण भंडार भी 26 करोड़ डॉलर बढ़कर 27.392 अरब डॉलर हो गया। आलोच्य सप्ताह के दौरान अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास आरक्षित निधि 5.8 करोड़ डॉलर बढ़कर 3.7 अरब डॉलर और विशेष आहरण अधिकार 20 लाख डॉलर की गिरावट के साथ 1.441 अरब डॉलर पर रहा।

# ITR में बड़ा बदलाव

## मकान के संयुक्त मालिक, 1 लाख सालाना बिजली बिल भरने वाले नहीं भर सकेंगे आईटीआर-1

***नई दिल्ली। आयकर रिटर्न फॉर्म के उपयोग में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। घर का संयुक्त मालिकाना अधिकार रखने वाले, साल भर में एक लाख रुपये का बिजली बिल भरने और विदेश यात्राओं पर दो लाख रुपये से अधिक खर्च करने वाले व्यक्तिगत करदाता अब सामान्य आईटीआर- 1 फॉर्म में आयकर रिटर्न नहीं भर सकेंगे।***

ऐसे करदाताओं को दूसरे फॉर्म में रिटर्न भरना होगा, जिन्हें आने वाले दिनों में अधिसूचित किया जाएगा। सरकारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है।सरकार आम तौर पर हर साल अप्रैल महीने में आयकर रिटर्न भरने के फॉर्म की अधिसूचना जारी करती है, लेकिन सरकार ने इस बार आकलन वर्ष 2020-21 के लिए तीन जनवरी को ही अधिसूचना जारी कर दी। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार 50 लाख रुपये तक की सालाना कमाई करने वाले आम निवासी व्यक्ति आईटीआर-1 'सहज' फॉर्म भर सकते हैं।

इसी प्रकार व्यवसाय और पेशे से हाने वाली अनुमानित और 50 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले हिन्दू अविभाजित परिवार, एलएलपी को छोड़कर अन्य कंपनियां, व्यक्तिगत करदाता आईटीआर-4 सुगम में रिटर्न भरते हैं।

लेकिन ताजा जारी अधिसूचना के मुताबिक इसमें दो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास घर का संयुक्त मालिकाना अधिकार है तो वह आईटीआर-1 या आईटीआर-4 में अपना रिटर्न नहीं भर सकता है। दूसरे, जिनके पास बैंक खाते में एक करोड़ रुपये से अधिक जमा राशि है, जिन्होंने विदेश यात्राओं पर दो लाख रुपये खर्च किए हैं अथवा सालभर में एक लाख रुपये या अधिक बिजली का बिल भरा है, उनके लिए आईटीआर-1 में रिटर्न भरना वैध नहीं होगा। ऐसे करदाताओं को अलग फॉर्म भरना होगा, जिसे जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।

# नवनीत के ब्रांड युवा की नई पहचान का अनावरण

*मुंबई। आईपीटी नेटवर्क*

***नवनीत एज्युकेशन लिमिटेड के लोकप्रिय स्टेशनरी ब्रांड युवा ने नए प्रतीक चिन्ह और प्रचार वाक्य के साथ अपने आप को अभिनव रूप में प्रस्तुत किया है। युवा का नया प्रचार वाक्य है- सोचो , सृजन करो।***

युवा का यह नया प्रतीक चिन्ह और प्रचार वाक्य हर भारतीय युवाओं के भीतर निहित जन्मजात रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है और उन्हें विचारक और सृजनशील बनने में सक्षम और प्रेरित करता है। प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मकता वास्तव में एक विशेष शक्ति है,जिसे ब्रांड के नए स्वरुप द्वारा व्यक्त किया गया है। भारतीय युवाओं के मन मस्तिष्क और खुदरा स्टेशनरी व्यवसाय में ब्रांड युवा को एक मजबूत स्थिति प्रदान करना ,इस नई पहचान का उद्देश्य है। युवा की यह नई पहचान उसके स्टेशनरी और गैर-स्टेशनरी उत्पादों की समकालीनता को विशेष रूप से दर्शाता है। वर्तमान समय में भारतीय युवाओं की आवश्यकताओं को समझते हुए ब्रांड युवा अपने उत्पादों में नित अभिनव परिवर्तन कर रहा है।ब्रांड का प्रतीक चिन्ह परमाणु के केंद्र से प्रेरित है ।

परमाणु का केंद्र रचनात्मकता का स्रोत है । यह प्रतीक चिन्ह ब्रांड युवा की मूल प्रेरणा 'ऊर्जा और गतिशीलता' को दर्शाता है। ब्रांड युवा की नई पहचान के संदर्भ में युवा के मुख्य स्ट्रेटजी ऑफिसर श्री अभिजीत सान्याल ने कहा -हमारा मानना है कि युवा हमारे भविष्य की नींव है और हम उन्हें सृजनशील बनने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं।

हमारे ब्रांड युवा का प्रत्येक उत्पाद भारतीय युवाओं की विचारधारा , उनके जोश और उत्साह को व्यक्त करता है। इस लोकप्रिय ब्रांड को नई पहचान देने की इस यात्रा का हिस्सा बनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह ब्रांड युवा को सफलता की ऊँचाई तक पहुँचाने के लिए सहायक सिद्ध होगी ।

# सरकार की नीतियों के खिलाफ दस केंद्रीय ट्रेड यूनियन हड़ताल पर

**नयी दिल्ली।** केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ दस ट्रेड यूनियनों के सदस्य बुधवार को देशव्यापी हड़ताल पर चले गए हैं। आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) की महासचिव अमरजीत कौर ने कहा कि इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के सदस्यों के साथ विभिन्न क्षेत्रीय महासंघ भी हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय यूनियनों में एटक, इंटक, सीटू, एआईसीसीटीयू, सेवा, एलपीएफ समेत अन्य शामिल हैं। उन्होंने पीटीआई-भाषा को बताया, 'हम महंगाई, सार्वजनिक कंपनियों की बिक्री, रेलवे, रक्षा, कोयला समेत अन्य क्षेत्रों में 100 प्रतिशत एफडीआई और 44 श्रम कानूनों को संहिताबद्ध करने (श्रम संहिता) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।' सरकार की नीतियों के खिलाफ अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली इस

हड़ताल में करीब 25 करोड़ लोगों के भाग लेने का अनुमान व्यक्त किया गया है। कौर ने कहा कि हमारी अन्य मांगों में सभी के लिए 6000 रुपये न्यूनतम पेंशन, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थम मूल्य (एमएसपी) और लोगों को राशन की पर्याप्त आपूर्ति शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बारिश आंदोलन पर असर नहीं डाल सकी है। श्रमिक राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में जुलूस निकालेंगे और योजना के मुताबिक, कर्मचारी आईटीओ पर एकत्र होंगे और फिर यहां से जुलूस निकालेंगे। कौर ने कहा, 'हमें पूरे देश भर से खबरें मिल रही हैं। भेल के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। ऑयल यूनियन हड़ताल पर है। पूर्वोत्तर, ओडिशा, पुडुचेरी, केरल और महाराष्ट्र में बंद की स्थिति है।'

## एक हजार से अधिक लोगों ने कराया स्वतंत्र निदेशक के डेटाबैंक में पंजीकरण

**नयी दिल्ली। एजेंसी**

कंपनियों में स्वतंत्र निदेशकों की उम्मीदवारी के लिये शुरू किये गये डेटा बैंक में अब तक 1,000 से अधिक लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। कंपनी कानून के तहत स्वतंत्र निदेशकों के पंजीकरण के लिये एक पोर्टल बनाया गया है। डेटा बैंक मौजूदा स्वतंत्र निदेशकों और नये बनने वाले स्वतंत्र निदेशक के लिये पात्र उम्मीदवारों का एक प्रकार की रिपाजिटरी होगी। कारपोरेट कार्य मंत्रालय के तहत बनाये गये 'दि इंडियन इंस्टीट्यूट आफ कारपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए)' इस डेटाबैंक पोर्टल की देखरेख करता है। अधिकारी ने बताया कि दिसंबर 2019 में शुरू होने के बाद से इस पोर्टल में 1,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। कुछ खास श्रेणियों को छोड़कर अन्य को पंजीकरण के बाद आनलाइन एक स्वः आकलन परीक्षा को पास करना होता है।

## रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए निगरानी नियमों में संशोधन किया

**मुंबई।** भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए निरीक्षण कार्रवाई रूपरेखा (एसएएफ) में संशोधन किया है। इसका मकसद कुछ सहकारी बैंकों के वित्तीय संकट का समाधान करने में तेजी लाना है। पंजाब एंड महाराष्ट्र को - ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक में धोखाधड़ी सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया है। इससे बैंक के नौ लाख से अधिक खाताधारकों को परेशानी हुई। आरबीआई ने अधिसूचना में कहा, 'प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, शहरी सहकारी बैंकों में वांछित सुधार लाने के लिए निरीक्षण कार्रवाई रूपरेखा को तर्कसंगत बनाने का फैसला किया गया है।' केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि वह संशोधित रूपरेखा के तहत शहरी सहकारी बैंक की कुल संपत्ति / पूंजी और मुनाफे , परिसंपत्ति की गुणवत्ता की निगरानी करना जारी रखेगा। संशोधित नियमों के तहत, शहरी सहकारी बैंक का शुद्ध एनपीए उसके शुद्ध कर्ज के छह प्रतिशत से ज्यादा हो जाने पर बैंक को निरीक्षणात्मक कार्रवाई व्यवस्था के तहत लाया जा सकता है। इसमें दबाव में फंसी संपत्ति की गंभीरता को देखते हुये रिजर्व बैंक उनकी कर्ज देने की क्षमता में कटौती कर सकता है। इसके साथ ही अन्य सुरक्षा उपाय भी किये जा सकते हैं। किसी भी शहरी सहकारी बैंक को लगातार दो वित्तीय वर्षों के दौरान घाटा होने पर अथवा उसके आय- व्यय खाते में संचित घाटा होने की स्थिति में भी एसएएफ व्यवस्था के तहत लाया जा सकता है।

## ITR-1 फॉर्म में हुए ये 6 बड़े बदलाव

# आईटीआर में टैन और पासपोर्ट नंबर भी देना होगा

**नई दिल्ली। एजेंसी**

आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म को बीते 3 जनवरी, 2020 को अधिसूचित कर दिया। इस साल आईटीआर फॉर्म-1 में कई तरह के बदलाव हुए हैं। हम उन 6 बदलावों से आपको अवगत कराने जा रहे हैं, जो आपको आईटीआर-1 फॉर्म में दिखेंगे।

### 1. पासपोर्ट डीटेल्स

इस साल ITR-1 फॉर्म में पासपोर्ट नंबर (अगर आयकर दाता के पास उपलब्ध हो) भी भरना होगा। फॉर्म में यह नया नियम जोड़ा गया है। आईटीआर-1 फॉर्म को हालांकि वे नहीं भर सकते हैं, जिन्होंने विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये या उससे अधिक रकम खर्च किए हों।

### 2. नियोक्ता का TAN नंबर

अब आईटीआर-1 फॉर्म में आपसे आपके नियोक्ता के बारे में विस्तृत जानकारियां मांगी जाएंगी। हालांकि, पिछले साल आईटीआर-1 में ड्रॉप डाउन मेन्यू से केवल नेचर ऑफ एंप्लॉयमेंट जैसे गवर्नमेंट, पीएसयू, पेंशनर्स, अन्य चुनना पड़ता था। अगर आपका नियोक्ता टैक्स (टीडीएस) काटता है तो इस साल से आईटीआर-1 भरने के दौरान आपको टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर (TAN) देना अनिवार्य होगा। अन्य विवरणों में नाम, नेचर ऑफ एंप्लॉयमेंट तथा एंप्लॉयर का अड्रेस देना होगा।

### 3. किरायेदार का पैन या आधार नंबर

अगर आपने अपनी किसी संपत्ति को किराये पर लगाया है तो आपको अपने किरायेदार का पैन या आधार नंबर देना होगा, अगर उपलब्ध हो तो।

### 4. आईटीआर-1 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया घटा

वित्त वर्ष 2019-20 का आईटीआर-1 फॉर्म उन लोगों द्वारा इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है, जिनके पास घर का संयुक्त मालिकाना अधिकार होगा। पिछले साल घर का संयुक्त मालिकाना अधिकार रखने वाले लोग भी आईटीआर-1 फॉर्म भर सकते थे। इसी तरह इस साल वे लोग भी आईटीआर-1 नहीं भर सकते हैं, जो किसी कंपनी में निदेशक हैं या किसी गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर में निवेश कर रखा है।

### 5. अपने घर का पूरा अड्रेस

अब आईटीआर-1 फॉर्म में आपको अपने घर का पूरा पता देना होगा।

### 6. अनरियलाइज्ड रेंट का डीटेल्स

अनरियलाइज्ड रेंट यानी हाउजिंग प्रॉपर्टी से मिलने वाली उस रकम का डीटेल्स भी देना होगा, जो किसी कारण मकान मालिक को नहीं मिल पाया है।

स्वामी विवेकानंद जयंती (12 जनवरी) पर विशेष

# धर्म का अर्थ है प्रत्यक्ष अनुभूति

**धर्म सीखने का नहीं, बल्कि शुद्ध रूप से प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। सच्चा धर्म वही होता है, जो परमात्मा और आत्मा की अनुभूति करा सके। जिसने अनुभव किया, उसी ने धर्म को जाना**

स्वामी विवेकानंद

**भक्ति** के दो विभाग हैं। एक वैधी भक्ति, जो विधिमयी या अनुष्ठानात्मक होती है और दूसरी मुख्या या पराभक्ति। अत्यंत निम्न श्रेणी से लेकर उच्चतम श्रेणी तक की उपासना के सभी रूपों का समावेश 'भक्ति' शब्द में होता है।

भक्ति का यह बाहरी भाग आत्मा को उन्नति के मार्ग में सहायता देने के लिए नितांत आवश्यक है। मनुष्य यदि सोचे कि मैं कूद कर एकदम उच्चतम अवस्था में पहुंच जाऊंगा, तो यह उसकी बड़ी भूल है। यदि बालक सोचे कि मैं एक दिन में वृद्ध बन जाऊंगा, तो यह उसका अज्ञान है। मैं आशा करता हूं कि तुम सदा इस बात का ध्यान रखोगे कि धर्म न तो पुस्तकों में है और न तर्कवाद में। तर्क-सिद्धांत, आप्त वाक्य, शास्त्राज्ञा, धार्मिक अनुष्ठान, ये सब धर्म के सहायक होते हैं, पर असली धर्म तो साक्षात्कार ही है। हम सब कहा करते हैं कि 'ईश्वर है।'

क्या तुमने ईश्वर को देखा है? यही प्रश्न है। तुम किसी मनुष्य को यह कहते सुनते हो कि 'स्वर्ग में एक ईश्वर है।' तुम उससे पूछते हो कि क्या तुमने ईश्वर को देखा है। यदि वह कहता है कि 'हां, मैंने ईश्वर को देखा है', तो तुम उस पर हंसोगे और उसे पागल कहोगे। धर्म अधिकांश लोगों के लिए एक प्रकार की बौद्धिक सम्मति देने मात्र में ही समाप्त हो जाता है। मैं इसे धर्म नहीं कहता। तुम कहते हो कि आत्मा है। क्या तुमने आत्मा को देखा है? हम सबमें आत्मा है, पर उसे देख नहीं पाते, यह कैसी बात है? तुमको इस प्रश्न का उत्तर देना होगा व आत्मा को देखने का उपाय निकालना होगा। यदि कोई सच्चा धर्म है, तो उसे हमें अपने आप में ही आत्मा, ईश्वर और सत्य का दर्शन करा सकने में समर्थ होना चाहिए।...

तुम इस बात का ध्यान रखो कि धर्म न बातों में है, न सिद्धांतों में और न पुस्तकों में, वह है प्रत्यक्ष अनुभव में। वह 'सीखना' नहीं है, 'होना' है। 'चोरी मत करो', इसे सब जानते हैं, पर इससे क्या? इसे तो यथार्थ में उसी ने जाना, जिसने चोरी नहीं की। धर्म अनुभव करना है और मैं तुमको ईश्वर का उपासक तभी कहूंगा, जब तुम इस आदर्श को सिद्ध करने में समर्थ हो जाओगे। साक्षात्कार या प्रत्यक्षानुभूति की यह शक्ति ही धर्म की निर्णायक है।... अतः धर्म का ये पहला चरण वैधी भक्ति, उपासना की निचली श्रेणी है।

उपासना के ये निम्न स्तर क्या हैं? ये अनेक हैं। उस अवस्था में पहुंचने के लिए, जिसमें हम ईश्वर का अनुभव कर सकेंगे, हमें साकार वस्तु के माध्यम से जाना होगा- ठीक उसी तरह, जैसेकि बच्चे प्रथम साकार वस्तुओं का अभ्यास करके उसके बाद क्रमशः भाववाचक की ओर जाते हैं। यदि तुम किसी बालक को 'दो पंचे दस' बताते हो, तो वह नहीं समझता। पर तुम उसे दस चीजें दो और दो-दो चीजें पांच बार उठाने से दस कैसे हुए, यह दिखा, तो वह उसे ठीक ठीक समझ लेगा।

**(रामकृष्ण मठ, द्वारा प्रकाशित 'विवेकानंद साहित्य संचयन' के अध्याय 'प्रतीकों का महत्व' से)**

# हर क्षण को नया करने का नाम अध्यात्म

**नया दिन अगले ही दिन पुराना हो जाता है। लेकिन आप किसी क्षण को नया करने की तरकीब जान जाएं, तो फिर हर क्षण नया हो जाएगा। यह तभी होगा, जब आप चीजों की बजाय खुद को नया करने की कोशिश करें। खुद को नया करने का मार्ग अध्यात्म बताता है, भौतिकता नहीं**

दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं- एक वे जो अपने को नया करने का राज खोज लेते हैं, और एक वे जो अपने को पुराना बनाए रखते हैं और चीजों को नया करने में लगे रहते हैं। जिसको भौतिकवादी कहना चाहिए, यह वह आदमी है, जो चीजों को नए करने की तलाश में है। भौतिकवादी और अध्यात्मवादी में एक ही फर्क है- अध्यात्मवादी रोज अपने को नया करने की चिंता में संलग्न है, क्योंकि उसका कहना यह है कि अगर मैं नया हो गया तो इस जगत में मेरे लिए कुछ भी पुराना न रह जाएगा, क्योंकि जब मैं ही नया हो गया तो पुराने का स्मरण करने वाला भी न बचा, पुराने को देखने वाला भी न बचा। हर चीज नई हो जाएगी।

और भौतिकवादी कहता है कि चीजें नई करो, क्योंकि स्वयं के नए होने का तो कोई उपाय नहीं है। नया मकान बनाओ, नई सड़कें लाओ, नए कारखाने, नई सारी व्यवस्था करो। सब नया कर लो, लेकिन अगर आदमी पुराना है और चीजों को पुराना करने की तरकीब उसके भीतर है, तो सब चीजों को पुराना कर ही लेगा। फिर हम इस तरह धोखे पैदा करते हैं।

अध्यात्म

ओशो

कितनी देर नया दिन टिकता है? कल फिर पुराना दिन शुरू हो जाएगा। लेकिन एक दिन के लिए हम अपने को झटका देकर- जैसे झाड़ लेना चाहते हैं सारी राख को, सारी धूल को, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये धोखे जुड़े हुए हैं। पुराना चित्त नए की तलाश से जुड़ा हुआ है। चाहिए ऐसा कि रोज नया चित्त हो सके। कैसे हो सकता है?

तब नया साल न होगा, नया दिन न होगा; नए आप होंगे। तब कोई भी चीज पुरानी नहीं हो सकती। जो आदमी निरंतर नए में जीने लगे, उस जीवन की खुशी का हिसाब आप लगा सकते हैं? वही रास्ता, कल जिससे गुजरा था, आज गुजर कर फिर भी नए फूल देख लेता हो, नए पत्ते देख लेता हो- उन्हीं वृक्षों पर, उसी सूरज में नया उदय देख लेता हो, उसी सांझ में नई बदलियां देख लेता हो, जो आदमी रोज नए को ईजाद कर सकता है भीतर से, उस आदमी की खुशी का हम कोई अंदाज नहीं लगा सकते।

वैसा आदमी फिर बोर नहीं होगा, बाकी सब लोग ऊब जाएंगे। पुराना उबाता है।

हर साल पुराना साल वापस लौट आता है। इससे हमारी आकांक्षा का तो पता चलता है, लेकिन हमारी समझदारी का पता नहीं चलता। आकांक्षा तो हमारी है कि नया दिन हो, वर्ष में एक ही हो, तो भी बहुत। पर ऐसी क्या मजबूरी है? अगर एक दिन को नया करने की तरकीब पता चल जाए, तो हम हर दिन को नया क्यों नहीं कर सकते?

एक फकीर के पास कोई आदमी गया था और उसने उससे पूछा कि मैं कितनी देर के लिए शांत होने का अभ्यास करूं? उस फकीर ने कहा, एक क्षण के लिए शांत हो जाओ। बाकी की तुम फिक्र मत करो। उस आदमी ने कहा, एक क्षण में क्या होगा? उस फकीर ने कहा, जो एक क्षण में शांत होने की तरकीब जान लेता है, वह पूरी जिंदगी शांत रह सकता है, क्योंकि एक क्षण से ज्यादा किसी आदमी के हाथ में दो क्षण कभी होते ही नहीं। एक क्षण ही हाथ में आता है, जब आता है। अगर एक क्षण को मैं जादू कर सकूं, और नया कर सकूं, और शांत कर सकूं, और आनंद से भर सकूं, तो मेरी पूरी जिंदगी आनंदित हो जाएगी, क्योंकि एक ही क्षण मेरे हाथ में आने वाला है सदा। उतनी तरकीब मैं जानता हूं कि एक क्षण को मैं कैसे नया कर लूं। एक क्षण को नया करना जो जान ले, उसकी पूरी जिंदगी नई हो जाती है।

> वही सूरज रोज नहीं उगता। जो कल था, वह कल विदा हो गया है। तो थोड़ा तलाश करते रहें, जो राख जम जाती है पुराने की, उसको हटा कर नीचे के अंगारे की खोज करते रहें कि नया क्या है? और नए का सम्मान करना सीखें तो नया प्रकट होगा।

पहली तो बात यह है कि प्रतिपल नए की खोज की हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि क्या नया है? हम पूछते हैं, क्या पुराना है? हमारे मन में प्रश्न होना चाहिए क्या नया है? और अगर हमारे मन में यह प्रश्न हो, तो ऐसा कोई भी क्षण नहीं है, जिसमें कुछ नया न आ रहा हो। सुबह सूरज को उठ कर देखें। जो सूर्योदय आज हुआ है, वह कभी भी नहीं हुआ था। सूर्योदय रोज हुआ है, लेकिन जो आज हुआ है, वह कभी भी नहीं हुआ था। न ऐसे बादलों के रंग कभी पहले हुए थे, न आगे कभी होंगे। न सूरज, जैसा आज की सुबह उगा है, ऐसा कभी उगा था, न उग सकता है।

नए को खोजें, थोड़ा देखें कि यह सूरज कभी उगा था? और आप चकित खड़े रह जाएंगे कि आप इस भ्रम में ही जी रहे थे कि रोज वही सूरज उगता है। वही सूरज रोज नहीं उगता। जो कल था, वह कल विदा हो गया है। तो थोड़ा तलाश करते रहें, जो राख जम जाती है पुराने की, उसको हटा कर नीचे के अंगारे की खोज करते रहें कि नया क्या है? और नए का सम्मान करना सीखें तो नया प्रकट होगा। अगर सम्मान न करेंगे, तो राख ही प्रकट होगी। अंगारा प्रकट कहां हुआ, अंगारा भीतर छिप जाएगा। नए का सम्मान करें।

जिंदगी में सब है- वहां राख भी है पुराने की, वहां अंगार भी है नए का, वहां चीजें मर भी रही हैं, पुरानी हो रही हैं, वहां नए का जन्म भी हो रहा है। वहां वृद्ध भी हैं, वहां बच्चे भी हैं। वहां जन्म भी है, मृत्यु भी है। वहां कुछ विदा हो रहा है, कुछ आ रहा है। आप क्या खोजने गए हैं, इस पर निर्भर करता है। अगर आप मृत को खोजने गए, तो आप मरघट पर पहुंच जाएंगे।

लेकिन एक तरफ जीवन जन्म भी ले रहा है रोज, वहां आप खोजने नहीं गए हैं- जहां सूरज की नई किरण फूटती है, कली फूटती है, नया-नया रोज कुछ हो रहा है। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि तीन सौ पैंसठ दिन ही नए हो सकते हैं। प्रतिपल नया हो सकता है। नए की तैयारी और नए का सम्मान और नए के लिए मन का द्वार खुला होना चाहिए। और जो व्यक्ति एक बार नए के लिए अपने मन के द्वार को खोल लेता है, आज नहीं, कल वह पाता है कि नए के पीछे परमात्मा प्रवेश कर गया, क्योंकि परमात्मा अगर कुछ है, तो जो निरंतर नया है, उसी का नाम है।

**(सौजन्यः ओशोधारा नानक धाम, मुरथल)**

## अमेरिका, ईरान में युद्ध की आशंका से चाय उद्योग चिंतित

# बासमती चावल का निर्यात रुका

**कोलकाता। एजेंसी**

अमेरिकी ड्रोन द्वारा ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराए जाने के बाद दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव का असर भारतीय निर्यात पर दिखना शुरू हो गया है। घरेलू व्यापार संगठन ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स असोसिएशन (AIREA) ने निर्यातकों से हालात सामान्य होने तक तेहरान को बासमती चावल का निर्यात रोकने को कहा है। वहीं चाय उद्योग ने चिंता जताते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच तनाव से तेहरान को होने वाले चाय के निर्यात पर भी असर पड़ सकता है। अमेरिका ने शुक्रवार को एक ड्रोन हमले में ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया, जिसके बाद मध्य-पूर्व में युद्ध की आशंका गहरा गई है। टी बोर्ड के चेयरमैन पी. के. बेजबरूआ ने कहा, 'अगर अमेरिका तथा ईरान के बीच युद्ध होता है तो इसका असर पड़ेगा।' सीआईएस (कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स) के बाद ईरान भारत के सबसे बड़े चाय आयातक देश के रूप में उभरा है।

### पिछले साल 5 करोड़ किलो चाय निर्यात

टी बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, ईरान को नवंबर 2019 तक 5.043 करोड़ किलोग्राम चाय का आयात किया गया, जबकि सीआईएस देशों को कुल 5.280 करोड़ किलोग्राम चाय का निर्यात किया गया। उन्होंने कहा, 'ज्यादा कीमतें मिलने के कारण पिछले साल चाय निर्यातकों ने ईरानी बाजार का रुख किया था।' आईटीए के पूर्व चेयरमैन एवं एमडी तथा गुडरीक ग्रुप के सीईओ अतुल अस्थाना ने कहा, 'अगर लड़ाई होती है तो ईरान को चाय का निर्यात नहीं हो पाएगा।'

### ...तो फिर सीआईएस देशों को निर्यात पर विचार

अधिकारियों ने हालांकि कहा है कि अगर ईरान को चाय के निर्यात में बाधा आती है तो इंडस्ट्री फिर से सीआईएस देशों को निर्यात पर विचार करेगा, लेकिन कीमतों में बहुत ज्यादा मोलभाव नहीं होगा।

### बासमती चावल का निर्यात निलंबित

अमेरिका तथा ईरान के बीच ताजा तनाव को देखते हुए घरेलू व्यापार संगठन ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स असोसिएशन (AIREA) ने निर्यातकों से कहा है कि जब तक हालात सामान्य न हो जाएं, तब तक वे ईरान को बासमती चावल का निर्यात रोक दें। AIREA ने कहा है कि भारत के बासमती चावल का ईरान एक प्रमुख आयातक देश है और अगर निर्यात पर असर पड़ता है तो घरेलू कीमतों पर असर पड़ेगा जिसका प्रभाव किसानों पर देखने को मिलेगा।

### 10,800 करोड़ का बासमती चावल निर्यात

पिछले वित्त वर्ष में भारत ने कुल 32,800 करोड़ रुपये का बासमती चावल निर्यात किया था, जिसमें से लगभग 10,800 करोड़ रुपये कीमत का चावल ईरान को निर्यात किया था।

### निर्यातकों को जारी की गई अडवाइजरी

AIREA के प्रेजिडेंट नाथी राम गुप्ता ने कहा, 'मौजूदा परिस्थिति में ईरान को बासमती चावल का निर्यात करना संभव नहीं है। हमने अपने सदस्यों को एक अडवाइजरी जारी किया है, जिसमें उनसे ऐहतियात बरतने तथा हालात सामान्य होने तक उन्हें ईरान को चावल निर्यात नहीं करने को कहा है।'

## अब तक 12,000 टन प्याज का आयात, राज्यों को 49-58 रुपये किलो के भाव पेशः पासवान

**नयी दिल्ली।** सरकार ने प्याज की आपूर्ति बढ़ा कर इसकी कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए अब तक 12,000 टन प्याज का आयात किया है। सरकार राज्यों को इसे 49 से 58 रुपये किलो के भाव पर पेश कर रही है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने मंगलवार को यह जानकारी दी । उन्होंने संवाददाताओं से कहा , ''हमने तुर्की और अफगानिस्तान जैसे देशों से अभी तक 12,000 टन प्याज का आयात किया है।'' सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की ट्रेडिंग कंपनी एमएमटीसी के माध्यम से प्याज का आयात कर रही है और निजी आयातकों को भी सुविधा दे रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल को पहले ही 1,000 टन आयातित प्याज दिया जा चुका है। इस महीने के अंत तक और 36,000 टन विदेशी प्याज की खेप पहुंचने की उम्मीद है। मंत्री ने कहा कि इससे कीमतों का दबाव कम करने में मदद मिलेगी। पिछले दो महीनों से प्याज 100 रुपये किलो के दायरे में था पर अब आयातित प्याज और नई खरीफ की फसल की आवक से प्याज का बाजार नरम होने लगा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में प्याज का भाव मंगलवार को 70 रुपये किलो पर था। गत 19 दिसंबर को यह 118 रुपये किलो पर चल रहा था। इसी तरह मुंबई में प्याज कीमत 120 रुपये घटकर अब 80 रुपये प्रति किलो पर आ गयी है। खरीफ के प्याज की फसल 25 फीसदी घटने से प्याज का बाजार चढ़ा हुआ है।

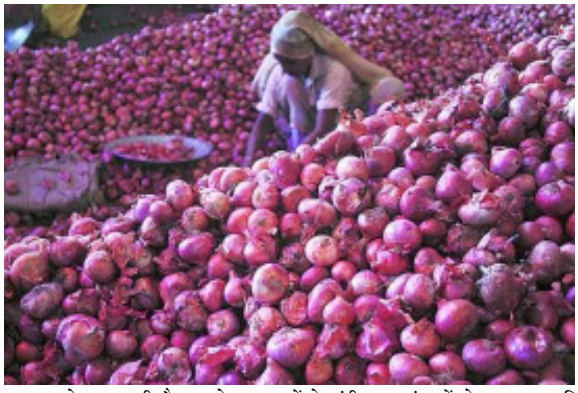

## इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सुविधाओं के लिये ईवीआई टेक्नालाजीज ने बीएसएनएल के साथ हाथ मिलाया

**नयी दिल्ली।** इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये बैटरी चार्ज सुविधायें उपलब्ध कराने वाली कंपनी ईवीआई टेक्नालाजीज (ईवीआईटी) ने सोमवार को कहा कि उसने बैटरी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र की भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के साथ समझौता किया है। दोनों के बीच 10 साल का सहमति ज्ञापन समझौता हुआ है। समझौते के तहत ईवीआईटी देशभर में बीएसएनएल के पांच हजार से अधिक स्थानों पर बैटरी चार्ज करने की सुविधायें उपलब्ध करायेगी। इसमें बैटरी की अदला-बदली के साथ ही बैटरी चार्ज करने की सुविधायें उपलब्ध होंगी। कंपनी ने एक वक्तव्य में कहा है कि समझौते के तहत ईवीआईटी शुरुआत में होने वाला पूरा निवेश खुद करेगी। इसमें बैटरी चार्जिंग सुविधा परिचालन और रखरखाव सभी कुछ शामिल है। इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बीएसएनएल इसके साथ ही बैटरी चार्जिंग सुविधाओं के लिये जरूरी स्थान और बिजली कनेक्शन उपलब्ध करायेगी। बीएसएनएल महाराष्ट्र के मुख्य महा प्रबंधक कुमार मिश्रा ने कहा कि इस पहल से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और कार्बन उत्सर्जन कम होगा। समझौते के तहत पहला चार्जिंग स्टेशन अगले महीने महाराष्ट्र और हरियाणा में खोलने की योजना है।

## दूरसंचार उद्योग का सरकार से सस्ता कर्ज दिलाने का आग्रह

**नयी दिल्ली।** नकदी की तंगी से जूझ रहे दूरसंचार उद्योग ने सोमवार को सरकार से दूरसंचार कंपनियों को कम ब्याज दरों पर कर्ज उपलब्ध कराने का आग्रह किया ताकि उनकी पूंजीगत लागत को कम किया जा सके। दूरसंचार उद्योग के प्रतिनिधियों ने दूरसंचार विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करके अपने सुझाव दिए। दूरसंचार विभाग ने उद्योग को मंगलवार तक लिखित में सिफारिशें भेजने के लिए कहा है। विभाग इन मांगों को वित्त मंत्रालय को भेजेगा ताकि बजट में इन पर विचार किया जा सके। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इन मांगों के बारे में कहा कि, लाइसेंस शुल्क और सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष (यूएसओएफ) शुल्क में कटौती सहित अधिकांश मांगें पहले जैसी ही हैं। अधिकारी ने कहा कि एक सिफारिश इनपुट लाइन क्रेडिट से जुड़ी है। इसके अलावा , उद्योग ने दूरसंचार कंपनियों को कम दरों पर वित्तपोषण की सुविधा देने , लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) से जीएसटी हटाने तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट का भुगतान करने भी मांग की है। उद्योग ने सरकार से आग्रह किया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए दूरसंचार टावरों को संयंत्र और मशीन की परिभाषा में शामिल किया जाए।

## केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खनिज कानून संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी

**नयी दिल्ली।** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को खनिज कानून संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने संवाददाताओं को बताया कि इस अध्यादेश के माध्यम से खनिज विकास एवं नियमन अधिनियम 1957 और कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 में संशोधन का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से कोयला एवं खनन क्षेत्र में नये युग का सूत्रपात होगा। जोशी ने बताया कि भारत में कोयले की मांग काफी अधिक है लेकिन बड़े पैमाने पर इसका आयात किया जाता है।

# 150 प्राइवेट ट्रेनों से आ सकता है 22 हजार करोड़ रुपये का निवेश, विदेशी कंपनियों को भी ठेका

**नई दिल्ली।** भारतीय रेल और नीति आयोग ने निजी ऑपरेटरों को 100 रेल-रूटों पर 150 प्राइवेट ट्रेनों के परिचालन की अनुमति दिए जाने को लेकर रोडमैप तैयार कर लिया है। इसको लेकर एक डिस्कशन पेपर भी लाया गया है, जिसमें बताया गया है कि इससे 22,500 करोड़ रुपये का निवेश आ सकता है।

'निजी भागीदारी: यात्री रेलगाड़ियां' शीर्षक वाले डिस्कशन पेपर में कहा गया है कि 100 मार्गों की पहचान की गई है, जिन पर निजी इकाइयों को 150 गाड़ियों के परिचालन की अनुमति देने से 22,500 करोड़ रुपये का निवेश आएगा।

इन रूटों में मुंबई सेंट्रल-नई दिल्ली, नई दिल्ली-पटना, अहमदाबाद-पुणे और दादर-वड़ोदरा के इंदौर-ओखला, लखनऊ जम्मू तवी, चेन्नै-ओखला, आनंद विहार-भागलपुर, सिंकदराबाद-गुवाहाटी और हावड़ा-आनंद विहार शामिल हैं। इन 100 रूटों को 10-12 समूहों में बांटा गया है। दस्तावेज

के अनुसार, निजी कंपनियों को अपनी गाड़ियों में बाजार के अनुसार किराया वसूल की छूट होगी।

वे इन गाड़ियों में अपनी सुविधा के हिसाब से विभिन्न श्रेणियों की बोगियां लगाने के साथ-साथ रूट पर उनके ठहराव वाले स्टेशनों का भी चयन कर सकेंगे। दस्तावेज में कहा गया कि ट्रेनों के निजीकरण से आधुनिक प्रौद्योगिकी लाने और रख-रखाव की लागत कम करने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलने के साथ ही मांग व आपूर्ति की खाई को कम करने में भी मदद मिलेगी। इस दस्तावेज के अनुसार, ट्रेनों का परिचालन करने वाले संभावित निकाय घरेलू के साथ ही विदेशी भी हो सकते हैं।

अभी नई दिल्ली-लखनऊ के बीच भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस चल रही है। तेजस को चलाने की जिम्मेदारी आईआरसीटीसी को मिली है। इसमें यात्रियों को कई नई सुविधाएं दी जा रही हैं। ट्रेन के लेट होने पर यात्रियों को मुआवजे का भी प्रावधान है।

# UAE में 7 अरब बैरल तेल भंडार का पता चला ऑयल रिजर्व में छठे पायदान पर पहुंचा

**अबू धाबी। एजेंसी**

यूनाइनटेड अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में हाइड्रोकार्बन के नए भंडार का पता चला है। खलीज टाइम्स के मुताबिक, यहां करीब 7 अरब बैरल कच्चा तेल और 58 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस का भंडार छिपा है। इस भंडार के पता लगने के बाद विश्व में गैस और तेल भंडार के मामले में UAE छठे पायदान पर पहुंच गया।देश का कच्चा तेल भंडार अब 105 अरब बैरल अबू धाबी सुप्रीम पेट्रोलियम काउंसिल (SPC) ने सोमवार को घोषणा की कि नए भंडार के पता लगने के बाद देश का कच्चा तेल भंडार अब 105 अरब बैरल और पारंपरिक गैस का भंडार 273 ट्रिलियन क्यूबिक फीट हो गया है।

### OPEC का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक UAE

वर्तमान में UAE OPEC (ऑर्गनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज) देशों में तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और रोजाना 30 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है। इससे ज्यादा तेल का उत्पादन सऊदी अरब और इराक करते हैं। वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायेद अल नहयान ने इस खोज के लिए अबू धाबी नैशनल ऑयल कंपनी की कोशिशों की सराहना की।

# Aadhaar में मोबाइल नंबर और ई-मेल का वेरिफिकेशन हुआ आसान

### इस ऐप से होगा काम

**नई दिल्ली।** आधार (Aadhaar) के साथ अपने मोबाइल नंबर (Mobile Number) और ई-मेल (E-mail) का वेरिफिकेशन करना जरूरी है। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। UIDAI ने आधार में मोबाइल नंबर और ई-मेल के वेरिफिकेशन के प्रोसेस को आसान बना दिया है। अब आप आपने किसी दोस्त या रिश्तेदार का वेरिफिकेशन भी आसानी से कर सकेंगे। इसके लिए आपके पास आधार का ऐप m-aadhaar डाउनलोड करना होगा। इस ऐप में आपको वेरीफाई ई-मेल और मोबाइल का ऑप्शन दिखेगा, जिस पर क्लिक कर मोबाइल और ईमेल के वेरिफिकेशन की

प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

### इसलिए जरूरी है ई-मेल/ मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन

यह सेवा आधार कार्ड धारकों और सेवा प्रदाताओं को यह जानने हेतु सक्षम करेगी कि आधार एक वैध संख्या है और निष्क्रिय नहीं है। आधार नंबर धारक का पंजीकृत मोबाइल नंबर आधार ऑनलाइन सेवाओं और आधार संबंधित फायदों के लिए आवश्यक है। निवासी पहले से पंजीकृत किया गया अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल पता सत्यापित कर सकते हैं।

### UIDAI ने शुरू की नई सर्विस

आधार यूजर्स की परेशानियों को दूर करने के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने 'Ask Aadhaar Chatbot' लॉन्च किया है। इसके जरिए यूजर्स आधार से जुड़ी अपनी शिकायतों और सवालों के जवाब पा सकता है।

# रफ्तार नहीं पकड़ पाई व्यापारियों के लिए लाई गई राष्ट्रीय पेंशन योजना

**नयी दिल्ली।** व्यापारियों और स्वरोजगार करने वाले लोगों के लिए पेश की गई राष्ट्रीय पेंशन योजना रफ्तार पकड़ने में विफल रही है। सरकार ने मार्च अंत तक इस योजना के तहत 50 लाख नामांकन का लक्ष्य रखा है, लेकिन अब तक सिर्फ 25,000 लोगों ने ही योजना के लिये पंजीकरण कराया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली से सिर्फ 84 व्यापारियों और स्वरोजगार वाले लोगों ने इस योजना के तहत पंजीकरण कराया है। वहीं केरल से 59, हिमाचल प्रदेश से 54, जम्मू-कश्मीर से 29 और गोवा से दो लोगों ने योजना के तहत पंजीकरण कराया है। अब तक योजना के तहत सबसे अधिक 6,765 पंजीकरण उत्तर प्रदेश से हुए हैं। आंध्र प्रदेश से 4,781, गुजरात से 2,915, महाराष्ट्र से 632, बिहार से 583, राजस्थान से 549, तमिलनाडु से 309, मध्य प्रदेश से 305 और पश्चिम बंगाल से 234 पंजीकरण हुए हैं। व्यापारियों और स्वरोजगार करने वाले लोगों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना) एक स्वैच्छिक और अंशदान आधारित केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। सरकार ने यह योजना 22 जुलाई, 2019 को शुरू की थी। इसके तहत 18 से 40 वर्ष की आयु के लोगों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद मासिक 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी।

योजना के तहत सरकार अंशधारकों के खातों में उनके द्वारा जमा कराई गई राशि के बराबर योगदान देगी। योजना को मिली ठंडी प्रतिक्रिया पर कनफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के महासचिव प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि योजना के तहत प्रवेश की आयु और प्रीमियम बढ़ाया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक व्यापारी योजना में शामिल होने को प्रोत्साहित हों। खंडेलवाल ने कहा कि तीस साल तक प्रीमियम देने के बाद मासिक 3,000 रुपये मिलेंगे, जिसकी शायद उस समय कोई कीमत नहीं होगी। 40 से 55 साल के व्यापारियों को योजना से बाहर क्यों रखा गया है? सरकार इस आयु वर्ग के लोगों के लिए प्रीमियम बढ़ा सकती है। उन्हें योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। कैट महासचिव ने सरकार को व्यापारियों के लिये एक अलग कोष बनाने का भी सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यापारी जीवन भर जितना कर सरकार को देता है उसमें से कुछ राशि से एक भविष्य निधि की तरह का कोष बनाया जाना चाहिये। इस कोष में से व्यापारी को 60 साल की आयु के बाद पेंशन देने की व्यवस्था हो सकती है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।